

बजट अनुमान 2015-2016

वर्ष 2015-16 का बजट अनुमान संशोधित अनुमानों पर ₹ 96,319 करोड़ की निवल वृद्धि को दर्शाता है। आयोजना-भिन्न व्यय ने ₹ 98,976 करोड़ की वृद्धि दर्शायी है। तथापि आयोजना व्यय में ₹ 2,657 करोड़ की वृद्धि रही है। अन्तर के लिए प्रमुख मदें नीचे दर्शायी गई हैं:

		(करोड़ रुपए)		
		संशोधित	बजट	घट-बढ़
		2014-15	2015-16	कमी(-)/ वृद्धि(+)
आयोजना-भिन्न				
1.	ब्याज भुगतान एवं ऋण चुकाना	411354	456145	(+) 44791
2.	राज्य सरकारों को अनुदान	79166	107559	(+) 28393
3.	रक्षा व्यय	222370	246727	(+) 24357
4.	पेंशन	81705	88521	(+) 6816
5.	पुलिस	48112	51791	(+) 3679
6.	पूँजी परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	7771	10582	(+) 2811
7.	उर्वरक सब्सिडी	70967	72969	(+) 2002
8.	खाद्य सब्सिडी	122676	124419	(+) 1743
9.	लाभांश राहत के लिए रेलवे को सब्सिडी	4002	4729	(+) 727
10.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान	452	1003	(+) 551
11.	डाक घाटा	6378	6665	(+) 287
12.	अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	158271	141090	(-) 17181
जोड़ आयोजना-भिन्न व्यय		1213224	1312200	(+) 98976
आयोजना				
1.	केन्द्रीय आयोजना	189766	260493	(+) 70727
2.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	278168	204784	(-) 73384
जोड़ आयोजना व्यय		467934	465277	(-) 2657
जोड़ व्यय				
(आयोजना+आयोजना भिन्न)		1681158	1777477	(+) 96319

आयोजना-भिन्न

- वृद्धि मुख्यतया बाजार ऋणों, नकदी प्रबंधन हुंडियों, राजकोषीय हुंडियों, और आरक्षित निधियों पर ब्याज के भुगतान हेतु अधिक आवश्यकता के कारण है।
- वृद्धि का कारण संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों के लिए उच्चतर प्रावधान करना तथा सीएसटी के चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कारण राजस्व हानियों के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करना है।
- रक्षा सेवाओं के प्रचालन संबंधी व्यय और पूंजीगत व्यय के तहत उच्चतर जरूरतों के कारण।

- वृद्धि का कारण रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल में खपाए गए कर्मचारियों के संबंध में पेंशन संबंधी भुगतानों के प्रति उच्चतर आवश्यकता है।
- आंतरिक सुरक्षा के कारण उच्चतर आवश्यकता।
- सीमावर्ती सड़कों के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और निर्माण कार्यों में उच्चतर निवेश के कारण।
- किसानों को रियायती दर पर विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री के अंतर्गत उच्चतर आवश्यकता के कारण।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु उच्चतर प्रावधानों के कारण।
- लाभांश राहत हेतु अर्हता प्राप्त रेल लाइनों के निर्माण के कारण।
- स्पेक्ट्रम के अभ्यर्षण पर बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम प्रभार लौटाने के कारण।
- वृद्धि का कारण डाक संबंधी प्रचालनों के लिए उच्चतर आवश्यकता है।

आयोजना

- वृद्धि का कारण कृषि, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विदेश मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एड्स नियंत्रण विभाग, गृह मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय प्रदान किया गया उच्चतर परिव्यय है।
- कमी का कारण कृषि और सहकारिता, पशुपालन, दुग्धोद्योग और मत्स्यपालन, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन आर्थिक कार्य विभाग, गृह मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, पंचायती राज, भू-संसाधन, कपड़ा, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा निर्मलीकरण, महिला एवं बाल विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के लिए केन्द्रीयकृत प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया परिव्यय है।